श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव 2015: आगामी मुद्दे और चुनौतियां

*डॉ. एम समता**

श्रीलंका में 8 जनवरी को संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में, विपक्ष के साझा उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरीसेना ने इक्यावन प्रतिशत मत प्राप्त करके पदधारी राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को हरा दिया, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति सैंतालीस प्रतिशत से थोड़ा अधिक (मत) प्राप्त कर सके। यह चुनाव भ्रष्टाचार और वर्ष 2005 से ही सत्ता पर आसीन राजपक्षे शासन की बढ़ती निरंकुशता के मुद्दों पर लड़ा गया था।

यह चुनाव महत्वपूर्ण था क्योंकि, पहली बार, किसी वर्तमान राष्ट्रपति ने श्रीलंका के संविधान में संशोधन करके तीसरे कार्यकाल की मांग की थी। संविधान में 18वां संशोधन वर्ष 2010 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान राष्ट्रपति को कितनी ही बार चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। यह चुनाव पिछले सितंबर में युवा प्रांतीय परिषद के चुनाव के दौरान युनाइटेड पीपल्स फ्रीडम एलायन्स (यूपीएफए) के (बेहतर) प्रदर्शन के बाद अपने वास्तविक समय से दो वर्ष पहले हुआ। युनाइटेड पीपल्स फ्रीडम एलायन्स (यूपीएफए) गठबंधन बहुत थोड़े अंतर से चुनाव में विजयी रहा और मतदान के हिस्सेदारी/प्रतिशत में भी कमी आई।

दूसरी बात, यह चुनाव लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) की हार के बाद दूसरा राष्ट्रपति चुनाव था। वर्ष 2010 के चुनावों में, राजपक्षे ने कुल किए गए मतदान का 57.88 प्रतिशत मत प्राप्त करके विपक्षी उम्मीदवार जनरल शरत फोंसेका के विरूद्ध जीत हासिल की। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) की सैन्य हार ने राजपक्षे के पक्ष में काम किया। यहां तक कि वर्ष 2010 के आम चुनाव में भी युनाइटेड पीपल्स फ्रीडम एलायन्स (यूपीएफए) गठबंधन को संसद में दो तिहाई बहुमत

मिला और इससे राजपक्षे को बिना किसी बाधा के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों को लागू करने का पूर्ण प्राधिकार प्राप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार के चुनाव में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) की सैन्य पराजय ने उनके पक्ष में काम नहीं किया। अल्पसंख्यक समुदायों के मतों ने राजपक्षे को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। तमिल और मुसलमान मिलकर श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत (श्रीलंका सरकार की 2012 की जनगणना के अनुसार) हैं।

बढ़ती मुद्रास्फीति, शिक्षित युवाओं के लिए आर्थिक अवसरों की कमी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों के विरूद्ध ग्रामीण जनता में असंतोष इस हार के कारण थे। उदाहरण के लिए, हालांकि राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पर है लेकिन वास्तव में इससे सिंहली ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और यह युवाओं को रोजगार प्रदान करने में भी असफल रहा। मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर), 2014 के अनुसार, श्रीलंका में पिछले दशक के दौरान 20 से 40 वर्ष की आयु वाले लोगों में बेरोजगारी दर लगभग 40 प्रतिशत थी। विदेशी कंपनियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किए गए उर्वरकों तथा इंधनों का उपयोग करने के बाद विशेषकर, राजारता क्षेत्र में लोगों की मौत की अनेक घटनाएं हुईं। भूमि-धारकों/भू-स्वामी की सहमति के बिना सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विदेशी कंपनियों को भूमि के स्वत: हस्तांतरण का भी एक मुद्दा सामने आया। इसलिए, ग्रामीण सिंहली जनसंख्या, जो वर्ष 2005 से ही राजपक्षे के पक्ष में एकजुट थी, ने अपना ध्यान अब आजीविका के मुद्दे की ओर मोड़ लिया है।

तमिल समुदाय ने भी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकांश तमिलों ने वर्ष 2005 और 2010 के चुनावों में राजपक्षे विरोधी रवैया/रूख अपनाया। वर्ष 2010 के चुनाव में तमिल राष्ट्रीय गठबंधन (टीएनए) ने केवल राजपक्षे को हराने के लिए विपक्षी उम्मीदवार जनरल शरत फोंसेका के पक्ष में मतदान करने का विकल्प चुना, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी उम्मीदवार जनरल शरत फोंसेका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के विरूद्ध अभियानों के लिए जिम्मेवार लोगों में से थे, जिसमें 40,000 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या भी हुई। तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले तमिल राष्ट्रीय गठबंधन (टीएनए) ने इस बार के चुनाव में भी विपक्षी उम्मीदवार के लिए मतदान करने का विकल्प चुना। उत्तरी प्रांत में मैत्रीपाला सिरीसेना के लिए बढ़चढ़ कर मतदान किया गया। उदारहरण के लिए, जाफना और वानी जिलों में मैत्रीपाल ने 70 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त किए। उत्तरी प्रांत में बढ़ते सैन्यकरण और युद्धप्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण में धीमी प्रगति के साथ-साथ वर्ष 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) की हार के पश्चात भी कोई ठोस

राजनीतिक समाधान प्रस्तुत करने में नाकामी ने राजपक्षे के विरूद्ध काम किया। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय द्वारा मैत्रीपाला सिरीसेना को दिया गया समर्थन जातीय सुलह/मेलमिलाप के साथ-साथ युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए तेज कार्यान्वयन की आशा में दिया गया था। यह देखना अभी बाकी है कि वे (मैत्रीपाला) तमिल समुदाय के साथ मेल-मिलाप के राष्ट्रीय प्रश्न को सुलझाने की क्या योजना बनाते हैं, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि जेथिका हेला उरूमाया (जेएचयू) सत्ता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की छूट दिए जाने के बिलकुल खिलाफ है।

तमिल अल्पसंख्यकों के अलावा, मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय ने भी राजपक्षे के विरूद्ध मतदान किया। पिछले वर्ष देश के दक्षिण में बेकसूर मुसलमानों पर सिंहली बौध संगठनों द्वारा हुए संगठित आक्रमणों के परिणामस्वरूप श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस ने राजपक्षे सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। यह तथ्य मुस्लिम बहुल पूर्वी प्रांत में मतदान प्रतिशत में भी प्रदर्शित हुआ है। उदाहरण के लिए, मैत्रीपाला सिरीसेना ने बट्टीकलोवा जिले में कुल किए गए मतदान (2,59,166) का लगभग 81 प्रतिशत से अधिक (मत) प्राप्त किया, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति को कुल किए गए मतदान का (केवल) 16 प्रतिशत (मत) मिला। सिंहली राष्ट्रवादी संगठनों जैसेकि बोदूबाला सेना (बीबीएस) जो मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध दंगों के लिए जिम्मेदार था, की भर्त्सना करने और उन्हें रोक पाने में राजपक्षे शासन-व्यवस्था की पूर्ण नाकामी ने भी राजपक्षे की उम्मीदवारी के विरूद्ध काम किया।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार की आलोचना करने में विपक्ष एकजुट था। यदि हम (चुनाव) अभियान के दौरान विपक्ष द्वारा प्रचारित मुद्दों को देखते हैं तो (पाते हैं कि) विपक्ष ने राजपक्षे परिवार को सीधे तौर पर निशाना बनाया, जो कई लोगों के अनुसार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त था और देश को क्षेत्र बाह्य शक्तियों को बेच रहा था। सिरीसेना ने अपने चुनाव घोषणापत्र में विदेश नीति के मुद्दे का मोटे तौर पर ज़िक्र किया है और घोषणापत्र के अनुसार "श्रीलंका की छवि गलत तथा अनुभवहीन विदेश नीति एवं कार्यनीतियों के कारण खराब हुई है", जिसके परिणामस्वरूप श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग पड़ गया। यह पश्चिम तथा यूरोप संघ से बढ़ती दूरी और उस अलगाव के संदर्भ में था, जिसका सामना श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कर रहा है। 1970 के दशक में, श्रीलंका उदारीकरण की नीतियों को अपनाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश था और ब्रेटन वुड्स संस्थाएं तब से ही देश की आर्थिक नीति को दिशानिर्देश देने में सहायक रहीं थीं। तथापि, चीन के साथ इस देश के बढ़ते संबंध और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के साथ युद्ध के दौरान और युद्ध के अंतिम चरण के बाद सरकार द्वारा किए गए तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण पिछले दशक में पश्चिम और श्रीलंका के बीच तनातनी बढ़ गई है।

चुनाव अभियान के दौरान, विपक्ष ने देश में चीन की भागीदारी के मुद्दे को भी सामने ला दिया। विपक्ष ने चीन द्वारा वित्तपोषित 1.34 अरब डॉलर की कोलंबो पत्तन सिटी परियोजना को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए निकाल फेंकने का संकल्प लिया। चीनी फर्मों द्वारा सड़कों का निर्माण करने में खर्च हुई धनराशि का मुद्दा भी था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 'भारत की इरकॉन (कंपनी) देश के उत्तर में एक सड़क परियोजना का कार्यान्वयन 25 लाख डॉलर प्रति किलोमीटर की लागत से कर रही है, जबकि चीनी कंपनी दक्षिण में रेलवे लाइनें 1 करोड़ 5 लाख डॉलर की लागत से बिछा रही है।' विपक्ष ने राजपक्षे सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश को दिवालिया बनाने का काम कर रही है। तथापि, परंपरागत रूप से, यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी), और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) की सरकारों ने वैचारिक मतभेद होने के बावजूद चीन के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध कायम रखे। यह देखने की आवश्यकता है कि क्या स्थानीय शिकायतें अथवा आर्थिक चेतना चीन के प्रति नई सरकार की नीति निर्धारित करेगी।

नई सरकार के समक्ष ये चुनौतियां हैं कि मैत्रीपाला सिरीसेना ने ग्रामीण सिंहली युवाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों से भी अपील की थी कि वे देश को दो चरणों में स्थिरता प्रदान करेंगे। पहले चरण में, एक राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार स्थापित की जाएगी, जिसमें ऐसे सभी राजनैतिक दलों और लोगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो तत्कालिक मुद्दों को सौ दिनों में सुलझाने के लिए सरकार में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। दूसरे चरण में, उन्होंने इस वर्ष होने वाले आम चुनावों के बाद प्रारूपित/तैयार किए जाने वाले छह वर्षीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से एक आदर्श देश के निर्माण का वायदा किया। मैत्रीपाला सिरीसेना को विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी), जेथिका हेला उरूमाया (जेएचयू), तमिल राष्ट्रीय गठबंधन (टीएनए) और डेमोक्रैटिक पार्टी के साथ-साथ श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) के सदस्यों का भी समर्थन मिला, जिसमें उन्होंने हाल तक महासचिव के रूप में सेवाएं दी थीं। उन्होंने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक दलों में एकता कायम करने का वायदा किया। तथापि, इस तथ्य के मद्देनजर यह एक कठिन कार्य होगा कि सिरीसेना का समर्थन कर रहे राजनीतिक दल महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा नहीं करते।

इस संदर्भ में, (यक्ष) प्रश्न यह है कि श्रीलंका में सरकार बदलने के बाद भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार का स्वरूप लेते हैं। दोनों देशों के बीच विकासात्मक सहायता वाले विकास सहयोग और आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग जारी रहने की संभावना है। तथापि, राजनीतिक रूप से संवेदनशील ऐसे मुद्दे हैं, जो भविष्य में भारत और श्रीलंका के संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि नई सरकार तमिल अल्पसंख्यकों के साथ सुलह/मेल-मिलाप की प्रक्रिया के संबंध में भारत की चिन्ताओं पर (कितना) ध्यान

देगी। श्रीलंका के संविधान के तेरहवें संशोधन का कार्यान्वयन एक ऐसा विकल्प है जिससे सत्ता विघटित होकर प्रांतों को मिल सकती है। तथापि, यह सच है कि अधिकांश सिंहली इस संशोधन के माध्यम से अल्पसंख्यकों तक सत्ता के पर्याप्त विघटन का समर्थन नहीं करते। इसलिए नए राष्ट्रपति को बड़े तथा छोटे राजनीतिक दलों को शामिल करके जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान हेतु राष्ट्रीय सहमति पैदा करने की दिशा में काम करना है। मछुआरों के मुद्दे का प्रश्न भी बना हुआ है और दोनों देशों को दोनों पक्षों के मछुआरों को शामिल करके किसी स्थायी समाधान की तलाश करने की आवश्यकता है।

*डॉ. एम समता विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।